

EXAM GENIUS

Presents

GENIUS CURRENT AFFAIRS

In Bilingual

24 June 2026



Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !



Ques: RBI has exempted banks from maintaining CRR and SLR on fresh Non-Resident External (NRE) Term Deposits of what minimum maturity period?

प्रश्न: RBI ने बैंकों को ताज़ा अनिवासी बाह्य (NRE) सावधि जमा (Term Deposits) पर CRR और SLR बनाए रखने से छूट दी है, बशर्ते उनकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि कितनी हो?

- A) 1 year or more / 1 वर्ष या अधिक
- B) 2 years or more / 2 वर्ष या अधिक
- C) 3 years or more / 3 वर्ष या अधिक
- D) 5 years or more / 5 वर्ष या अधिक
- E) 10 years or more / 10 वर्ष या अधिक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has exempted banks from maintaining Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) on fresh Non-Resident External (NRE) Term Deposits with a maturity of 3 years or more.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि वाली नई अनिवासी बाह्य (NRE) सावधि जमा पर नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखने से छूट दी है।
- The measure aims to attract foreign capital inflows and increase the availability of foreign currency resources with banks.
- इस कदम का उद्देश्य विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करना तथा बैंकों के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा संसाधनों को बढ़ाना है।
- The exemption will be available for deposits mobilised between 19 June 2026 and 30 September 2026.
- यह छूट 19 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच जुटाई गई जमाओं पर लागू होगी।
- RBI had earlier announced a similar exemption for fresh Foreign Currency Non-Resident (Bank) [FCNR(B)] deposits with maturities of 3 to 5 years.
- RBI इससे पहले 3 से 5 वर्ष की अवधि वाली नई Foreign Currency Non-Resident (Bank) [FCNR(B)] जमा पर भी CRR और SLR से छूट दे चुका है।





Ques: Which Central Public Sector Enterprise (CPSE) was recently granted Navratna status by the Government of India, becoming the 28th Navratna CPSE?

प्रश्न: भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया, जिससे वह 28वां नवरत्न CPSE बन गया?

- A) Chennai Petroleum Corporation Limited (CPCL) / चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- B) Oil India Limited (OIL) / ऑयल इंडिया लिमिटेड
- C) Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) / भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- D) Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) / हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
- E) Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) / मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Chennai Petroleum Corporation Limited has been granted Navratna Status by the Government of India.
- चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है।
- The announcement was made by the Ministry of Finance.
- इसकी घोषणा वित्त मंत्रालय द्वारा की गई।
- With this recognition, CPCL has become the 28th Navratna Central Public Sector Enterprise (CPSE) in India.
- इस मान्यता के साथ CPCL भारत का 28वां नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) बन गया है।
- Navratna status is awarded to high-performing CPSEs and provides them with greater financial and operational autonomy.
- नवरत्न का दर्जा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले CPSEs को दिया जाता है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्राप्त होती है।

About CPCL | CPCL के बारे में

- Chennai Petroleum Corporation Limited was formerly known as Madras Refineries Limited (MRL).
- CPCL का पूर्व नाम मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड (MRL) था।





Ques: The National Highways Authority of India (NHAI) recently launched the Multi-Lane Free Flow (MLFF) based tolling system at which toll plaza on the Delhi–Jaipur section of NH-48?

प्रश्न: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल ही में NH-48 के दिल्ली–जयपुर खंड पर किस टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) आधारित टोलिंग प्रणाली शुरू की है?

- A) Choryasi Toll Plaza, Gujarat / चोरयासी टोल प्लाजा, गुजरात
- B) Bakkarwala Toll Plaza, Delhi / बक्करवाला टोल प्लाजा, दिल्ली
- C) Daulatpura Toll Plaza, Rajasthan / दौलतपुरा टोल प्लाजा, राजस्थान
- D) Kherki Daula Toll Plaza, Haryana / खेड़की दौला टोल प्लाजा, हरियाणा
- E) Shahjahanpur Toll Plaza, Rajasthan / शाहजहांपुर टोल प्लाजा, राजस्थान

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The National Highways Authority of India has successfully launched the Multi-Lane Free Flow (MLFF) based tolling system at Daulatpura Toll Plaza on the Delhi–Jaipur section of NH-48.
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने NH-48 के दिल्ली–जयपुर खंड पर दौलतपुरा टोल प्लाजा में मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) आधारित टोलिंग प्रणाली सफलतापूर्वक शुरू की है।
- The MLFF system integrates Automatic Number Plate Recognition (ANPR) technology with FASTag-based Electronic Toll Collection.
- MLFF प्रणाली में ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तकनीक को FASTag आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के साथ एकीकृत किया गया है।
- This technology enables seamless toll collection without requiring vehicles to stop at toll plazas.
- यह तकनीक वाहनों को टोल प्लाजा पर रुके बिना निर्बाध रूप से टोल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है।
- Earlier, NHAI successfully implemented the MLFF system at Chorayasi Toll Plaza on the Surat–Bharuch section of NH-48.
- इससे पहले NHAI ने NH-48 के सूरत–भरूच खंड पर स्थित चोरयासी टोल प्लाजा में MLFF प्रणाली लागू की थी।





Ques: Under which mission is the Har Ghar Jal programme being implemented in India?

प्रश्न: भारत में हर घर जल कार्यक्रम किस मिशन के अंतर्गत लागू किया जा रहा है?

- A) Swachh Bharat Mission / स्वच्छ भारत मिशन
- B) Atal Bhujal Yojana / अटल भूजल योजना
- C) Jal Jeevan Mission / जल जीवन मिशन
- D) Namami Gange Programme / नमामि गंगे कार्यक्रम
- E) PM Krishi Sinchai Yojana / प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Under the Har Ghar Jal initiative, more than 16 crore rural households have received tap water connections across India.
- हर घर जल पहल के तहत भारत में 16 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्राप्त हुए हैं।
- The initiative has significantly improved access to safe and clean drinking water in rural areas.
- इस पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार किया है।
- Har Ghar Jal is implemented under the Jal Jeevan Mission launched by the Government of India.
- हर घर जल योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित की जाती है।
- The mission aims to provide Functional Household Tap Connections (FHTCs) to every rural household.
- इस मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) उपलब्ध कराना है।
- The achievement reflects major progress in improving public health, sanitation and quality of life in villages.
- यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार को दर्शाती है।
- The coverage now exceeds the population of several developed countries when compared collectively.
- यह कवरेज कई विकसित देशों की कुल जनसंख्या की तुलना में भी अधिक है।
- The milestone has been highlighted as part of the "12 Years of Naya Bharat Nirman" campaign.





Ques: Who has been appointed as the Chairperson of the National Statistical Commission (NSC) for a three-year term?

प्रश्न: राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के अध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Rajeeva Laxman Karandikar / राजीव लक्ष्मण करंदीकर
- B) Saibal Chattopadhyay / सैबल चट्टोपाध्याय
- C) Satyendra Bahadur Singh / सत्येन्द्र बहादुर सिंह
- D) Shubhabrata Das / शुभब्रत दास
- E) Madhavan Mukund / माधवन मुकुंद

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Appointments Committee of the Cabinet (ACC) has approved the appointment of Saibal Chattopadhyay as the Chairperson of the National Statistical Commission.
- मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है।
- His tenure will be for three years.
- उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
- Dr. Saibal Chattopadhyay is the former Director of Indian Institute of Management Calcutta.
- डॉ. सैबल चट्टोपाध्याय आईआईएम कोलकाता के पूर्व निदेशक रह चुके हैं।
- He succeeds Rajeeva Laxman Karandikar.
- उन्होंने राजीव लक्ष्मण करंदीकर का स्थान लिया है।
- Along with the Chairperson, three part-time members have also been appointed: Shubhabrata Das, Satyendra Bahadur Singh, and Madhavan Mukund.
- अध्यक्ष के साथ तीन अंशकालिक सदस्यों शुभब्रत दास, सत्येन्द्र बहादुर सिंह और माधवन मुकुंद की भी नियुक्ति की गई है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- NSC Established – 1 June 2005





- NSC की स्थापना – 1 जून 2005
- Operational Since – 12 July 2006
- कार्यशील – 12 जुलाई 2006
- Recommendation Basis – Rangarajan Commission
- स्थापना का आधार – रंगराजन आयोग (2001)
- Administrative Ministry – Ministry of Statistics and Programme Implementation
- प्रशासनिक मंत्रालय – सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
- NSC functions as the apex advisory body for strengthening India's official statistical system.
- NSC भारत की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।

EXAM
Genius





Ques: The Government e-Marketplace (GeM) signed an MoU with which organization to improve access to government procurement opportunities, especially in rural and underserved regions?

प्रश्न: सरकारी खरीद के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) Digital India Corporation / डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
- B) BharatNet / भारतनेट
- C) CSC e-Governance Services India Limited (CSC-SPV) / सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
- D) National Informatics Centre (NIC) / राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
- E) India Post Payments Bank (IPPB) / इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Government e-Marketplace, under the Ministry of Commerce and Industry, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with CSC e-Governance Services India Limited.
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC-SPV) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- The partnership aims to improve access to government procurement opportunities, especially for businesses in rural, remote, and underserved regions.
- इस साझेदारी का उद्देश्य ग्रामीण, दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों के व्यवसायों के लिए सरकारी खरीद अवसरों तक पहुंच को बेहतर बनाना है।
- Under the agreement, 50 GeM Suvidha Kendras (GSKs) will be established on a pilot basis through the CSC network.
- इस समझौते के तहत CSC नेटवर्क के माध्यम से 50 GeM सुविधा केंद्र (GSKs) पायलट आधार पर स्थापित किए जाएंगे।
- These centres will help sellers, entrepreneurs, and small businesses register and participate in government procurement processes.
- ये केंद्र विक्रेताओं, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पंजीकरण एवं भागीदारी में सहायता प्रदान करेंगे।





Ques: Which scheme aims to create more than 3.5 crore jobs over a two-year period by promoting formal employment and incentivizing job creation?

प्रश्न: कौन-सी योजना औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देकर तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करके दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियाँ सृजित करने का लक्ष्य रखती है?

- A) PM Employment Generation Programme (PMEGP) / पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम
- B) Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) / प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- C) Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) / प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
- D) National Career Service (NCS) / राष्ट्रीय करियर सेवा
- E) Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) / दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana aims to facilitate the creation of more than 3.5 crore jobs over a period of two years.
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) का उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है।
- Prime Minister Narendra Modi disbursed incentives amounting to approximately ₹2,400 crore under the scheme at Vigyan Bhawan, New Delhi.
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में योजना के तहत लगभग ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की।
- Around 1.92 crore beneficiaries are expected to be first-time entrants into the workforce.
- लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थियों के पहली बार कार्यबल में शामिल होने की संभावना है।
- Since August 2025, more than 70 lakh first-time employees have been brought into the formal workforce under PM-VBRY, with women accounting for nearly 30% of the beneficiaries.
- अगस्त 2025 से अब तक 70 लाख से अधिक प्रथम-बार कर्मचारी औपचारिक कार्यबल में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें लगभग 30% महिलाएँ हैं।





Ques: Which company was recently granted Navratna Central Public Sector Enterprise (CPSE) status, becoming the 29th Navratna in India?

प्रश्न: हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) का दर्जा प्रदान किया गया, जिससे वह भारत की 29वीं नवरत्न कंपनी बन गई?

- A) Bharat Electronics Limited (BEL) / भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
- B) Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) / मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
- C) Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE) / गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
- D) Cochin Shipyard Limited (CSL) / कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
- E) Bharat Dynamics Limited (BDL) / भारत डायनेमिक्स लिमिटेड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India has upgraded Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited to Navratna Central Public Sector Enterprise (CPSE) status.
- भारत सरकार ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSE) का दर्जा प्रदान किया है।
- With this recognition, GRSE has become the 29th Navratna CPSE in India.
- इस मान्यता के साथ GRSE भारत का 29वाँ नवरत्न CPSE बन गया है।
- GRSE functions under the Ministry of Defence.
- GRSE रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- Navratna status provides greater financial and operational autonomy to Central Public Sector Enterprises.
- नवरत्न का दर्जा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक वित्तीय एवं परिचालन स्वायत्तता प्रदान करता है।
- As per the government's Navratna announcement, GRSE reported an annual turnover of approximately ₹7,002 crore in FY 2025–26.
- सरकार की नवरत्न घोषणा के अनुसार, GRSE ने वित्त वर्ष 2025–26 में लगभग ₹7,002 करोड़ का वार्षिक कारोबार दर्ज किया।





Ques: According to the Energy Transition Index (ETI) 2026 released by the World Economic Forum (WEF), what was India's rank?

प्रश्न: विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (ETI) 2026 के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा?

- A) 60th / 60वाँ
- B) 65th / 65वाँ
- C) 70th / 70वाँ
- D) 75th / 75वाँ
- E) 80th / 80वाँ

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Energy Transition Index 2026 was published by the World Economic Forum.
- ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (ETI) 2026 को विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रकाशित किया गया।
- The index assessed a total of 120 countries.
- इस सूचकांक में कुल 120 देशों का मूल्यांकन किया गया।
- India improved by two positions to rank 70th with an overall score of 54.9.
- भारत ने दो स्थानों की छलांग लगाकर 54.9 अंक के साथ 70वाँ स्थान प्राप्त किया।
- India emerged as one of the top gainers in the ETI 2026 rankings.
- भारत ETI 2026 में सबसे अधिक प्रगति करने वाले देशों में शामिल रहा।
- Sweden topped the ETI 2026 with a score of 75.3.
- स्वीडन ने 75.3 अंक के साथ ETI 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया।
- Global energy transition readiness declined by 0.76%, marking its first decline in more than a decade.
- वैश्विक ऊर्जा संक्रमण तैयारी में 0.76% की गिरावट दर्ज की गई, जो एक दशक से अधिक समय में पहली गिरावट है।
- This decline occurred despite total energy investments reaching USD 3.3 trillion, including USD 2.3 trillion in clean energy investments.
- यह गिरावट तब दर्ज हुई जब कुल ऊर्जा निवेश 3.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर स्वच्छ ऊर्जा निवेश शामिल है।





Ques: The Kishau Multi-Purpose Dam Project, recently approved by six states, will be constructed on which river?

प्रश्न: हाल ही में छह राज्यों द्वारा सहमति प्राप्त किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना (Kishau Multi-Purpose Dam Project) किस नदी पर बनाई जाएगी?

- A) Ganga / गंगा
- B) Yamuna / यमुना
- C) Tons / टोंस
- D) Chambal / चंबल
- E) Betwa / बेतवा

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Union Home Minister Amit Shah chaired a meeting in New Delhi where six states reached a consensus on the long-pending Kishau Multi-Purpose Dam Project.
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें छह राज्यों ने लंबे समय से लंबित किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना पर सहमति व्यक्त की।
- The states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, and Rajasthan agreed to sign a Memorandum of Understanding (MoU) for implementing the project.
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई।
- The project will be built on the Tons River, the largest tributary of the Yamuna, at the Himachal Pradesh–Uttarakhand border.
- यह परियोजना टोंस नदी, जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, पर हिमाचल प्रदेश–उत्तराखंड सीमा पर बनाई जाएगी।
- The project is estimated to cost ₹15,000 crore.
- इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹15,000 करोड़ है।
- It is expected to play a major role in the rejuvenation of the Yamuna River by increasing the flow of clean water.
- यह परियोजना यमुना नदी के पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा स्वच्छ जल के प्रवाह को बढ़ाएगी।





Ques: Who has been elected as the Vice-President of the Financial Action Task Force (FATF), marking the first time India has secured this position?

प्रश्न: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, जिससे पहली बार भारत को यह पद प्राप्त हुआ है?

- A) T. V. Somanathan / टी. वी. सोमनाथन
- B) Sanjay Malhotra / संजय मल्होत्रा
- C) Ajay Seth / अजय सेठ
- D) Vivek Aggarwal / विवेक अग्रवाल
- E) Rajesh Kumar Singh / राजेश कुमार सिंह

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Vivek Aggarwal, currently serving as Secretary, Ministry of Culture, has been elected as the Vice-President of the Financial Action Task Force (FATF).
- विवेक अग्रवाल, जो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के सचिव हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के उपाध्यक्ष चुने गए हैं।
- This is the first time India has secured the Vice-Presidency of FATF.
- यह पहला अवसर है जब भारत को FATF का उपाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है।
- India became a full member of FATF in 2010.
- भारत 2010 में FATF का पूर्ण सदस्य बना था।
- In India, FATF-related matters are handled by the Department of Revenue under the Ministry of Finance.
- भारत में FATF से संबंधित मामलों का संचालन वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है।
- The Vice-President of FATF assists in guiding the organisation's work related to combating global financial crimes.
- FATF के उपाध्यक्ष वैश्विक वित्तीय अपराधों से निपटने संबंधी संगठन के कार्यों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।





Ques: Which Union Minister launched the Smart Warehousing System for foodgrain storage, described as the world's largest deployment of AI and IoT technologies in public sector warehousing?

प्रश्न: सार्वजनिक क्षेत्र के खाद्यान्न भंडारण में AI और IoT आधारित विश्व की सबसे बड़ी तैनाती वाले स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया?

- A) Shivraj Singh Chouhan / शिवराज सिंह चौहान
- B) Pralhad Joshi / प्रह्लाद जोशी
- C) Piyush Goyal / पीयूष गोयल
- D) Manohar Lal Khattar / मनोहर लाल खट्टर
- E) Dharmendra Pradhan / धर्मेंद्र प्रधान

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Union Minister Pralhad Joshi launched the Smart Warehousing System for foodgrain storage at Bharat Mandapam, New Delhi.
- केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में खाद्यान्न भंडारण हेतु स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम का शुभारंभ किया।
- The initiative represents the world's largest deployment of Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT)-based technologies in public sector foodgrain warehousing.
- यह सार्वजनिक क्षेत्र के खाद्यान्न भंडारण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित तकनीकों की विश्व की सबसे बड़ी तैनाती है।
- The project has been launched by the Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution.
- यह पहल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) द्वारा शुरू की गई है।
- The system has been implemented in 215 bag-based warehouses of the Central Warehousing Corporation.
- इस प्रणाली को केंद्रीय भंडारण निगम (CWC) के 215 बैग-आधारित गोदामों में लागू किया गया है।
- The Food Corporation of India will implement the system in 150 additional warehouses.





Ques: The Indian Army will participate in the multinational military exercise KHAAN QUEST 2026, which is being held in which country?

प्रश्न: भारतीय सेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 (KHAAN QUEST 2026) में भाग लेगी, जो किस देश में आयोजित किया जा रहा है?

- A) Kazakhstan / कज़ाखस्तान
- B) Mongolia / मंगोलिया
- C) Uzbekistan / उज़्बेकिस्तान
- D) South Korea / दक्षिण कोरिया
- E) Japan / जापान

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Indian Army (IA) contingent will participate in the Khaan Quest multinational joint military exercise.
- भारतीय सेना (IA) का दल खान क्वेस्ट (KHAAN QUEST) बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेगा।
- The exercise will be conducted at the Five Hills Training Area in Ulaanbaatar.
- यह अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलानबटार स्थित फाइव हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया जाएगा।
- The Indian Army contingent is being represented by troops from a battalion of the Jat Regiment.
- भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व जाट रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिक करेंगे।
- The exercise aims to enhance interoperability, peacekeeping capabilities, and cooperation among participating armed forces.
- इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली सेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता (Interoperability), शांति स्थापना कौशल और सहयोग को बढ़ाना है।

About KHAAN QUEST | खान क्वेस्ट के बारे में

- The exercise was first launched in 2003 as a bilateral exercise between the United States of America (USA) and the Mongolian Defence Forces.
- यह अभ्यास 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और मंगोलियाई रक्षा बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था।





Ques: India's first commercial-scale Coal-to-Ammonium Nitrate Facility is being developed at Lakhanpur, Odisha by which joint venture company?

प्रश्न: भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट (Coal-to-Ammonium Nitrate) परियोजना, लखनपुर (ओडिशा) में किस संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा विकसित की जा रही है?

- A) NTPC Green Energy Limited / एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
- B) Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited (BCGCL) / भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड
- C) Coal India Renewable Limited / कोल इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड
- D) GAIL India Limited / गैल इंडिया लिमिटेड
- E) Hindustan Urvarak & Rasayan Limited / हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a ₹25,016 crore Coal Gasification Project at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha.
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में ₹25,016 करोड़ की कोल गैसीफिकेशन परियोजना की आधारशिला रखेंगे।
- The project marks India's first commercial-scale Coal-to-Ammonium Nitrate Facility.
- यह परियोजना भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला-से-अमोनियम नाइट्रेट (Coal-to-Ammonium Nitrate) सुविधा है।
- The project is being developed by Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited.
- इस परियोजना का विकास भारत कोल गैसीफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (BCGCL) द्वारा किया जा रहा है।
- BCGCL is a joint venture between Coal India Limited and Bharat Heavy Electricals Limited.
- BCGCL, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) का संयुक्त उद्यम है।

About Coal Gasification | कोयला गैसीफिकेशन के बारे में

- Coal Gasification is a process that converts coal into Synthetic Gas (Syngas).
- कोयला गैसीफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयले को सिंथेटिक गैस (Syngas) में परिवर्तित किया





जाता है।

- Syngas mainly contains Carbon Monoxide (CO) and Hydrogen (H₂).
- सिंथेटिक गैस मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोजन (H₂) से मिलकर बनी होती है।
- Syngas can be used to manufacture Methanol, Urea, Ammonium Nitrate, Synthetic Natural Gas (SNG), Chemicals, and Petrochemicals.
- सिंथेटिक गैस का उपयोग मेथेनॉल, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG), रसायन तथा पेट्रोकेमिकल्स के निर्माण में किया जाता है।
- The project is expected to support India's energy security, reduce import dependence, and promote value addition in the coal sector.
- यह परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयात निर्भरता कम करने और कोयला क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Coal India Limited Established – 1975
- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की स्थापना – 1975
- CIL Headquarters – Kolkata
- CIL मुख्यालय – कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
- Bharat Heavy Electricals Limited Established – 1964
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) की स्थापना – 1964
- BHEL Headquarters – New Delhi
- BHEL मुख्यालय – नई दिल्ली।
- Odisha Capital – Bhubaneswar
- ओडिशा की राजधानी – भुवनेश्वर।





Ques: Who has been appointed as a Judge of the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) for a nine-year term (2026–2035)?

प्रश्न: अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण (ITLOS) में 9 वर्षीय कार्यकाल (2026–2035) के लिए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Neeru Chadha / नीरू चड्ढा
- B) Bimal N. Patel / बिमल एन. पटेल
- C) Harish Salve / हरीश साल्वे
- D) Dalveer Bhandari / दलवीर भंडारी
- E) T.S. Thakur / टी.एस. ठाकुर

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Renowned Indian jurist Bimal N. Patel has been elected as a Judge of the International Tribunal for the Law of the Sea for the 2026–2035 term.
- प्रसिद्ध भारतीय विधिवेत्ता बिमल एन. पटेल को अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण (ITLOS) में 2026–2035 कार्यकाल के लिए न्यायाधीश निर्वाचित किया गया है।
- He will officially assume office on 1 October 2026.
- वे 1 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण करेंगे।
- He will succeed Neeru Chadha, whose nine-year term ends in September 2026.
- वे नीरू चड्ढा का स्थान लेंगे, जिनका 9 वर्षीय कार्यकाल सितंबर 2026 में समाप्त हो रहा है।
- A total of seven judges were elected for the 2026–2035 term.
- 2026–2035 कार्यकाल के लिए कुल सात न्यायाधीशों का निर्वाचन किया गया।
- The newly elected judges represent India, Vietnam, Ghana, Tunisia, Russia, Brazil, and the Netherlands.
- नव-निर्वाचित न्यायाधीश भारत, वियतनाम, घाना, ट्यूनीशिया, रूस, ब्राज़ील और नीदरलैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- International Tribunal for the Law of the Sea Established – 1996
- ITLOS की स्थापना – 1996





- Headquarters – Hamburg
- मुख्यालय – हैम्बर्ग, जर्मनी
- President – Tomas Heidar (Iceland)
- अध्यक्ष – टोमस हेइदार (आइसलैंड)
- Vice-President – Neeru Chadha
- उपाध्यक्ष – नीरू चड्ढा
- ITLOS adjudicates disputes arising out of the interpretation and application of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
- ITLOS संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित विवादों का निपटारा करता है।
- UNCLOS is often referred to as the "Constitution of the Oceans."
- UNCLOS को अक्सर "महासागरों का संविधान" कहा जाता है।
- Germany Capital – Berlin
- जर्मनी की राजधानी – बर्लिन।

EXAM
Genius





IMPORTANT ONE - LINER Current Affairs

Government of India (GoI) constituted a Search-cum-Selection Committee under the chairmanship of Cabinet Secretary Dr. T.V. Somanathan, to recommend names for the chairperson and members of the National Sports Board (NSB), a key body formed under the National Sports Governance Act, 2025.

The United Arab Emirates (UAE) has fixed 15 years as the minimum age for creating and using personal social media accounts. The UAE has become the first Arab country to introduce a nationwide minimum age requirement for social media access.

Ministry of Defence has signed a contract worth Rs. 425 crore with Bharat Forge Limited for the procurement of 12 sets of 1.25 MW Marine Gas Turbine Generators (MGTGs) for the Indian Navy.

The Asian Development Bank has provided a USD 10 million loan to Schoolnet India Limited. The objective of the loan is to scale up digital learning infrastructure in 30,000 government schools across India. Under the project, computer laboratories will be installed in at least 1,000 government schools.

The Ministry of Defence approved the creation of two new independent NCC State Directorates in Andhra Pradesh and Jharkhand, increasing the total number from 17 to 19.





महत्वपूर्ण वन-लाइनर करंट अफेयर्स

भारत सरकार (GoI) ने 'नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, 2025' के तहत बनी मुख्य संस्था 'नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड' (NSB) के चेयरपर्सन और सदस्यों के नामों की सिफारिश करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी डॉ. टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक 'सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी' बनाई है।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 15 साल की उम्र तय की है। UAE सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए पूरे देश में कम से कम उम्र की शर्त लागू करने वाला पहला अरब देश बन गया है।

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 1.25 MW के 12 मरीन गैस टर्बाइन जेनरेटर (MGTG) खरीदने के लिए 'भारत फोर्ज लिमिटेड' के साथ 425 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है।

एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 'स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड' को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है। इस लोन का मकसद पूरे भारत में 30,000 सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट के तहत कम से कम 1,000 सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाई जाएंगी।

रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड में दो नए स्वतंत्र NCC स्टेट डायरेक्टरेट बनाने को मंजूरी दी है, जिससे इनकी कुल संख्या 17 से बढ़कर 19 हो गई है।